frame and legal action is taken against the defaulting units.

iii. Environmental guidelines have been evolved for siting and operation of industries.

iv. Fiscal incentives are provided for installation of pollution control equipment and also for the shifting of industries from congested areas.

v. Customs and excise duty exemptions are provided to the industries for pollution control/ monitoring equipment.

vi. A scheme for setting up of Common Effluent Treatment Plants (CETPs) in clusters of small-scale industrial units is under implementation. About 61 CETPs in various States have been approved by the Government.

vii. Public awareness campaigns on the effects of pollution have been launched.

viii. A network of about 290 ambient air quality monitoring stations in 90 cities and towns in the Country and 480 water quality monitoring stations have been set up. Monitoring data on air and water quality are documented.

ix. A programme for phasing out of lead content in petrol is under implementation. Unleaded petrol with catalytic converter fitted vehicles has been introduced in four metropolitan cities to begin with.

x. More stringent norms for vehicular emissions have been notified under the Motor Vehicles Rules, 1989.

xi. Ministry of Surface Transport has been asked to instruct Delhi Transport Corporation that polluting buses and those under lease by the State Transport Authorities should not outshed from 1st January, 1996.

ग्रामीण पुस्तकालय खोलना

227. **श्री अनन्तराय देवशंकर द्वेः** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार गांवों में ग्रामीण पुस्तकालय खोलने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(घ) क्या गुजरात सरकार ने इसी संबंध में कोई पेशकश की; और

(ङ) वर्ष 1995-96 के दौरान इस प्रस्ताव के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई): (क) सरकार "विद्यालय-सह-ग्राम पुस्तकालय" की एक योजना पर विचार कर रही है।

(ख) राज्य-वार प्रस्तावित वितरण संबंधी एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गुजरात सरकार ने प्रस्ताव का स्वागत किया है।

(ङ) संस्कृति विभाग के वर्ष 1995-96 के बजट में 3.00 करोड़ रुपये का प्रावधान था।

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान एक मार्गदर्शी स्कीम के रूप में ग्रामीण पुस्तकालयों का राज्य-वार प्रस्तावित वितरण

1.	आंध्र प्रदेश	33
2.	अरूणाचल प्रदेश	5
3.	असम	16
4.	बिहार	53
5.	गोवा	5
6.	गुजरात	19
7.	हरियाणा	10
8.	हिमाचल प्रदेश	5
9.	जम्मू एवं कश्मीर	5
10.	कर्नाटक	22
11.	केरल	17
12.	मध्य प्रदेश	35

13.	महाराष्ट्र	33
14.	मणिपुर	5
15.	मेघालय	5
16.	मिजोरम	5
17.	नागालैंड	5
18.	उड़ीसा	19
19.	पंजाब	11
20.	राजस्थान	23
21.	सिक्किम	5
22.	तमिलनाडु	25
23.	त्रिपुरा	5
24.	उत्तर प्रदेश	79
25.	पश्चिम बंगाल	34

संघ शसित क्षेत्र

1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3
2.	चंडीगढ़	3
3.	दादरा एवं नगरहवेली	3
4.	दमन एवं दीव	3
5.	दिल्ली	3
6.	लक्षद्वीप	3
7.	पांडिचेरी	3

योग : 500

मध्य प्रेदश में बेतवा नदी का प्रदूषण

228. **श्री राघवजी:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996 में मध्य प्रदेश की बेतवा नदी कितनी बार व्यापक रूप से प्रदूषित हुई है तथा प्रत्येक बार पता लगाए गए प्रदूषण के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रदूषण की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया गया था, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इसके सदस्यों के नाम क्या-क्या है, उसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की तथा इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अक्टूबर माह में भी प्रदूषण के स्तर की जांच की गई थी, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस नदी को बार-बार प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद): (क) वर्ष 1996 के दौरान मध्य प्रदेश में बेतवा नदी दो बार प्रदूषित पाई गई थी। पहली बार जुलाई, 96 और दूसरी बार अक्टूबर, 96 में। पहले मौके पर नदी जल की जैव रसायन आक्सीजन मांग, जो कि इसके प्रदूषण का सूचक है, 3 मिग्रा० / प्रति लीटर की जगह 7.0 से 10 मिग्रा० / प्रतिलीटर के बीच पायी गयी थी। दूसरे मौके पर प्रदूषण प्रवाल पुष्पों (एल्गल ब्लूम) की प्रवृत्ति के कारण हुआ था।

(ख) बेतवा नदी में प्रदूषण के कारणों का अध्ययन करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की एक समिति बनाई गई थी। इस समिति में शामिल अधिकारियों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है (नीचे देखिए)। समिति ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दिनांक 4.11.96 को प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशें संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(ग) अक्टूबर के महीने में प्रदूषण के स्तर की जांच की गई थी। शैवाल फूलों (एल्गल ब्लूम) की प्रवृत्ति को छोड़कर नदी जल गुणवत्ता सामान्य पाई गई जो आई०एस० 2296—1982 के वर्ग 'ग' / 'घ' को पूरा करता है।

(घ) नदी जल को प्रायः प्रदूषित होने से रोकने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

समिति के सदस्य

1. डॉ० पी० सी० सेठ, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
2. श्री डी० एल० नायक, अधीक्षण अभियंता, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
3. श्री ए० पी० श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
4. डॉ० बंसल अप्पल, मुख्य केमिस्ट, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
5. श्री आर० एस० कोरी, क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।